सम्पादकीय

रैगिंग का रोग

गुजरात में पाटन जिले के जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र अनिल मेथानिया की कथित रैगिंग से हुई मौत दर्दनाक तो है ही, शर्मसार करने वाली भी है। आखिर रैगिंग पर पाबंदी के बाद भी ऐसी घटनाएं कैसे घट जा रही हैं? पिछले दो वर्षों में अकेले गुजरात में रैगिंग की आठ घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी तीन दिन पहले इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज का एक वाकया सामने आया था, जिसमें पीजी छात्र अभिषेक मसीह ने लगातार रैगिंग की वजह से अपनी सीट छोड़ने का फैसला किया, मगर कॉलेज प्रबंधन ने अभिषेक के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और उसे इंसाफ दिलाने के बजाय उसके मूल प्रमाणपत्र लौटाने से ही इनकार कर दिया और इसके लिए उससे पहले 30 लाख रुपये की बॉन्ड राशि चुकाने की मांग कर डाली। अंततः अभिषेक को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जहां से उसे राहत मिली। अदालत ने कॉलेज डीन को न सिर्फ फौरन दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया, बल्कि अपनी कार्रवाई के संबंध में बाकायदा अदालत को सूचित करने की हिदायत भी दी।

अठारह साल के अनिल मेथानिया ने तो महज एक महीने पहले दाखिला लिया था। खबरों के मुताबिक, सीनियर छात्रों ने तीन घंटे तक उसे खड़ा रखा और फिर डांस करने को मजबूर किया, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा और थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब 15 सीनियर मेडिकल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कॉलेज ने उन सबको सस्पेंड भी कर दिया है। निस्संदेह, दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हो, मगर कॉलेज प्रबंधन को क्यों बख्शा जाना चाहिए? अनिल को मौत के मुंह में धकेलने का जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन भी कम नहीं है। आखिर कॉलेज में रैगिंग जारी है, इस बात से प्रबंधन कैसे गाफिल रहा? बताया जा रहा है कि सभी आरोपी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। यह जीएमईआरएस कॉलेज प्रबंधन की बड़ी नाकामी है कि वह इतने दिनों में इन नौजवानों को मानवीयता का बुनियादी पाठ भी न पढ़ा सकी। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ आरोपी छात्रों की नहीं, बल्कि कॉलेज प्रशासन के संबंधित ओहदेदारों की भी तय होनी चाहिए।

रैगिंग से होने वाली मौतों व हत्याओं ने अब तक न जाने कितने घरों के दीपक बुझा दिए हैं और अनिल की मौत बता रही है कि इस सिलसिले को तोड़ना अब कितना जरूरी हो गया है। यह बताने की जरूरत नहीं कि कितने परिश्रम के बाद एक किशोर एमबीबीएस की परीक्षा पास करता है। फिर उसके सपने यूं खत्म हो जाएं, तो यह सिर्फ उसका व उसके परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि समूचे देश का घाटा है। खासकर तब, जब हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की दरकार है, ताकि अपने नागरिकों को स्तरीय चिकित्सा सेवा मुहैया करा सकें। वैसे तो रैगिंग कहीं पर, किसी भी रूप में अवैधानिक है, फिर मेडिकल कॉलेजों में तो यह कहीं ज्यादा बड़ा गुनाह है। आखिर जिन डॉक्टरों में हम ईश्वर का दूसरा अक्स देखते हैं, वे साल-दो साल की पढ़ाई के बाद भी इतने संवेदनहीन कैसे बने रहते हैं कि अपने ही जूनियर साथी की जिंदगी से खेल जाते हैं? ऐसे डॉक्टर डिग्री लेकर मरीजों की, खासकर हाशिये के रोगियों की किस संवेदनशीलता से इलाज करेंगे? रैगिंग के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान की त्वरित आवश्यकता है, ताकि अनिल जैसी कीमती प्रतिभाएं यूं न मारी जाएं।

विशेष

रुपये की स्वीकार्यता बढ़ाने के उपाय, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाना होगा

रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए महंगाई पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। जब रुपये का मूल्य स्थिर रहेगा तभी दूसरे देश रुपये में व्यापार करेंगे। बांग्लादेश को श्रीलंका से व्यापार करना हो तो यह रुपये में तभी किया जाएगा जब भारत में महंगाई नियंत्रण में हो और रुपये का मूल्य स्थिर हो। महंगाई बढ़ने का मूल कारण सरकार की खपत है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य होने के साथ ही एकल ब्रिक्स करेंसी की चर्चा आगे बढ़ रही है। एकल करेंसी का अर्थ है कि सभी सहभागी देशों की मुद्रा के स्थान पर एकल ब्रिक्स मुद्रा का चलन शुरू किया जाए। जैसे पूर्व में जर्मनी में मार्क और फ्रांस में फ्रैंक मुद्रा चलती थी। यूरोपीय संघ बनने के बाद सभी राष्ट्रीय मुद्राओं का लोप हो गया और सभी यूरोपीय देश एक ही मुद्रा यूरो का उपयोग करने लगे।

यूरो मुद्रा लागू होने के बाद यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर और बैंकों को दी जाने वाली सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं। आज जर्मनी और फ्रांस का मौद्रिक नीति पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आज यदि फ्रांस चाहे कि उसके देश में ब्याज दर चार प्रतिशत हो, जबकि जर्मनी चाहे कि उसकी ब्याज दर छह प्रतिशत हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्याज दर यूरोपीय केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है।

एकल मुद्रा यूरो स्थापित करने के साथ-साथ सभी सहयोगी देशों के नागरिकों को दूसरे देशों में जाकर काम करने की भी छूट दी गई है। इस क्रम में एकल ब्रिक्स करेंसी का अर्थ यह होगा कि भारतीय रुपये एवं चीनी मुद्रा रेनमिनबी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इनके स्थान पर ब्रिक्स करेंसी का उपयोग होगा। तब ब्रिक्स का केंद्रीय बैंक ब्याज दर आदि का निर्णय लेगा।

चूंकि ब्रिक्स में चीन का दबदबा है और चीन की आय दूसरे देशों से बहुत अधिक है, इसलिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंक में भी चीन का ही दबदबा रहेगा। ऐसी सूरत में उसके द्वारा ऐसी नीतियां लागू की जाएंगी, जो चीन के हित में हों। इसलिए ब्रिक्स मुद्रा को बनाना अव्यावहारिक है, लेकिन रुपये की साख को सुधारा जा सकता है। वर्तमान में हमारा 86 प्रतिशत विदेश व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है, यद्यपि भारत के केवल 15 प्रतिशत निर्यात ही अमेरिका जाते हैं।

शेष 71 प्रतिशत भारत के निर्यात ऐसे हैं, जो अन्य देशों को होते हैं, परंतु उन्हें भी डॉलर में किया जाता है। यदि भारत ने जर्मनी को सौ रुपये का माल बेचा तो बिक्री के बिल पर सौ रुपये न लिखकर केवल 1.1 डॉलर लिखा जाएगा। जर्मनी का क्रेता डॉलर खरीदेगा और उसे भारत को देगा। भारत का विक्रेता उस डॉलर को बेचकर रुपये प्राप्त करेगा। इस प्रक्रिया में भारत और जर्मनी दोनों को बड़ी मात्रा में डॉलर रखने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में डॉलर को अनायास ही बड़ा लाभ होता है।

प्रश्न है कि डॉलर का वर्चस्व किस आधार पर टिका है और निर्यात रुपये में क्यों नहीं किया जाता? वास्तव में रुपये जैसी किसी भी मुद्रा को विश्व व्यापार का माध्यम बनाने के लिए तीन जरूरतें पूरी करनी होंगी। पहली यह कि वह मुद्रा विश्व के तमाम देशों में स्वीकार्य हो। दूसरी जरूरत यह है कि हमारे रुपये की कीमत स्थिर रहे। मान लीजिए आज रुपये और डॉलर की विनिमय दर 80.1 है। आपने 80 लाख रुपये या एक लाख डॉलर के माल का आयात किया, जिसे डॉलर में किया गया, लेकिन आपके आर्डर देने के बाद डॉलर की कीमत बढ़ गई।

ऐसे में अब आपको उसी एक लाख डॉलर के माल का आयात करने के लिए अधिक रुपये अदा करने होंगे। इसी प्रकार धन के संग्रह के लिए भी मुद्रा का स्थिर रहना जरूरी होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने सौ करोड़ रुपये डॉलर में रखे हुए हैं और कुछ समय बाद डॉलर टूट गया तो उसे अनावश्यक हानि होगी। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार उस मुद्रा में किया जाता है, जो स्थिर रहे। यह ध्यान रहे कि अमेरिका द्वारा डॉलर के वर्चस्व की आड़ में विभिन्न देशों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

यदि भारत को अमेरिकी डॉलर के शिकंजे से निकलना है और चीन के शिकंजे में नहीं पड़ना है तो जरूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हो। इससे विश्व के हर देश में हमारे रुपये की स्वीकार्यता बढ़ेगी। वर्तमान में अपनी अर्थव्यवस्था का आकार अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार छोटा है, इसलिए हमें अमेरिका अथवा चीनी मुद्रा के दबदबे के बीच चयन करना पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर को छोड़कर चीन की रेनमिनबी को अपनाना कुएं से निकल कर खाई में गिरने जैसा होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बुनियादी संरचना में भारी निवेश किया है, लेकिन हमने रिसर्च में निवेश कम किया, जिसके कारण नई तकनीक के सृजन में हम पीछे हैं। अपने देश में सामाजिक तनाव अधिक है और पर्यावरण की स्थिति कमजोर है, जिसके कारण विदेशी लोग यहां आना नहीं चाहते और पर्याप्त विदेशी निवेश नहीं आ रहा।

रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए महंगाई पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। जब रुपये का मूल्य स्थिर रहेगा, तभी दूसरे देश रुपये में व्यापार करेंगे। बांग्लादेश को श्रीलंका से व्यापार करना हो तो यह रुपये में तभी किया जाएगा, जब भारत में महंगाई नियंत्रण में हो और रुपये का मूल्य स्थिर हो। महंगाई बढ़ने का मूल कारण सरकार की खपत है, जिसे पोषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भारी संख्या में नोट छापकर सरकार को उपलब्ध कराता है। अतः सरकार को अपनी खपत भी कम करना पड़ेगी।

साफ है कि जब तक हम रिसर्च में निवेश, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण और सरकारी खपत को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक रुपया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं बन सकेगा और हमें मजबूरन किसी दूसरी मुद्रा में अपना विदेशी व्यापार करना पड़ेगा, चाहे डॉलर हो या चीन की रेनमिनबी। हालांकि भारत द्विपक्षीय समझौतों से दूसरे देशों से सीधे रुपये में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, जो सही है, परंतु यह आज की जरूरतों से बहुत कम है। बिना अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किए हम अपने रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं बना पाएंगे।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

प्रदेश

'राष्ट्रीय युवा समागम' कार्यक्रम के पोस्टर का किया विमोचन

राजनीति एवं लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका का बताया महत्व

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

राजधानी में गुरुवार को भारत युवा वाहिनी द्वारा आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय युवा समागम कार्यक्रम की पोस्टर लॉन्च एवं प्रेस कांफ्रेंस गतिविधि का आयोजन जानकी पैराडाइज में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम के पोस्टर का विमोचन प्रवीण यादव चेयरमैन नगर निगम ग्रेटर, निशांत सुरोलिया पार्षद वार्ड नं. 57, सुरेंद्र चतुर्वेदी महासचिव सी.एम.आर.डी., अंशुमान सक्सेना भूतपूर्व महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, गौरव गौड़ फैशन कोरियोग्राफर, सुमन लता लोहिया पूर्व पार्षद, मोहन रिचा सैनी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, संजय सक्सेना संपादक युवा जगत, अपूर्व सक्सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत युवा वाहिनी द्वारा किया गया।

कार्यकम के प्रारम्भ में आगन्तुक अथितियों का स्वागत वाहिनी के जिला अध्यक्ष दिलीप गहलोत, जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र चतुर्वेदी,

जिला सचिव डॉ. सोनिका पारीक, जिला संगठन सचिव विकास सिंह तंवर और डॉ. जयेश जैन आदि द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रवीण यादव चेयरमैन नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने युवाओं को लोकतंत्र में एवं राजनीति में आने का आहवान किया, उनका मानना है कि आने वाला भारत युवाओं का देश है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं की महती भूमिका है। सुरेंद्र ने अपने भाषण में युवाओं को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपूर्व सक्सेना ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय युवा समागम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम दिनांक 6 दिसम्बर 2024 को जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र में आयोजित किया जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि इस कार्यक्रम में विशिष्ठ प्रेरक वक्ता, राजनैतिक नेतृत्व कर्ता अपने विचार प्रकट करेंगे। इस कार्यकम में विभिन्न क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जायेगा।

उन्होने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय राजनीति एवं लोकतंत्र की सशक्ता हेतु युवाओं की भूमिका पर केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग लेगें।

दीपक एडवरटाइजिंग की उपलब्धि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य भारत की नं. 1 क्रिएटिव और मीडिया एजेंसी दीपक एडवरटाइजिंग को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हुई कठिन चयन प्रक्रिया में दीपक एडवरटाइजिंग सूचीबद्ध हुई है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकल्पों का प्रचार, प्रसार करने के लिए होने वाले इवेंट्स के प्रमोशन में एजेंसी की सक्रिय भागीदारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि दीपक एडवरटाइजिंग मध्य भारत की एकमात्र आईएनएस, प्रसार भारती एवं सीबीसी द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी है और इंडियन रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आईआईएम, अवंतिका गैस लि, एलआईसी जैसे अन्य महत्वपूर्ण सरकारी महकमों को भी सेवाएं दे रही है। एमडी दीपक जेठा ने बताया कि एजेंसी अपनी क्रिएटिव व डेडिकेटेड टीम, अपने विजन, प्रतिबद्धता, उत्कृष्ट क्लाइंट सर्विसेज के कारण सदा सफलता के पथ पर अग्रसर रही है। गत माह एजेंसी ने 28 वर्ष पूर्ण किये हैं जिसके बाद मिलने वाली यह उपलब्धि अहम है। एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री में प्रमुखता के साथ काम कर रही दीपक एडवरटाइजिंग एजेंसी क्रिएटिव एडवरटाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, प्रिंट मीडिया, आउटडोर व कम्युनिकेशन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर गवर्मेंट और प्राइवेट क्षेत्र के क्लाइंट्स को सेवाएं दे रही है।

नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में 75 वर्षीय व्यक्ति ने जीती पैरोटिड ट्यूमर की जंग

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

जयपुर के एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को पैरोटिड ट्यूमर का सामना करना पड़ा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। यह ट्यूमर पैरोटिड ग्रंथि (कान के पास स्थित) में था और उसकी स्थिति बेहद असामान्य थी। यह गहरे भाग में था और पैराफैरिंजियल स्पेस तक फैल गया था। इस चुनौतीपूर्ण केस को डॉ. तेज प्रताप सिंह और उनकी ओटी व एनेस्थीसिया टीम ने सफलतापूर्वक संभाला और मरीज को नया जीवन दिया।

मरीज के गले के पिछले हिस्से में गांठ थी, जिससे उनकी आवाज में बदलाव आ गया था और उन्हें निगलने में दिक्कत हो रही थी। जांच के बाद पता चला कि यह पैरोटिड ट्यूमर था, जो गले के गहरे भाग में पैराफैरिंजियल स्पेस तक फैला हुआ था, जहां कैंसर होना बहुत ही दुर्लभ होता है। ट्यूमर के चेहरे की नस (फेशियल नर्व) के पास होने से चेहरा लकवाग्रस्त होने का खतरा था। यहां तक कि क्रैनियल नर्व्स को चोट लगने से बोलने और निगलने में परेशानी या जीवन घातक स्थितियां हो सकती थीं। यह गांठ दिमाग को रक्त देने वाली नली से चिपकी हुई थी जिसके कारण उसके आधे शरीर में लकवा हो सकता था। ट्यूमर की जटिलता को देखते हुए हमने सर्जरी के लिए गर्दन के रास्ते का विकल्प चुना। डॉ. तेज प्रताप सिंह ने बताया कि अधिक उम्र और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, मरीज की सर्जरी सफल रही। यह सर्जरी बेहद नाजुक थी क्योंकि चेहरे की नस को नुकसान पहुंचने का खतरा था। चार घंटे चली इस सर्जरी में हमने पूरे मामले में अत्यंत सावधानी बरती। ऑपरेशन के बाद मरीज ने तेजी से रिकवरी की और तीन दिनों के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. प्रदीप कुमार गोयल ने कहा कि हर मरीज का इलाज अलग होता है और हम सभी पहलुओं पर ध्यान देकर सबसे बेहतर उपचार योजना तैयार करते हैं।

टेढ़े पैरों को सीधा करने का सही आंकलन हो सकेगा

एसएमएस में जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए अब नई तकनीक

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

एसएमएस में जॉइंट रिप्लेसमेंट (जोड़ प्रत्यारोपण) के ऑपरेशन में अब नई तकनीक का उपयोग शुरू किया है। घुटने और कुल्हों के जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन में अब डॉक्टर्स कम्प्यूटर नेविगेशन तकनीक का उपयोग कर सकेंगे। इस तकनीक के शुरू होने से मरीजों का ऑपरेशन करने के दौरान चीरा भी सामान्य से छोटा लगाना पड़ेगा। इससे न केवल ब्लड लॉस कम होगा और टेढ़े पैरों को सीधा करने की सटिकता का भी अच्छे से आंकलन हो सकेगा। एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर और एचओडी डॉ. आर.सी. बंसीवाल ने बताया- ये तकनीक अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही उपयोग में आती है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह की तकनीक का उपयोग राजस्थान में एसएमएस में शुरू किया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उनके मरीजों के ऑपरेशन के दौरान होता है, जिनके घुटनों या कुल्हों का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। इस तकनीक मशीन के उद्घाटन के अवसर पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी और एसएमएस के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी भी मौजूद थे।

एसएमएस के असिस्टेंट प्रोफेसर और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉ. मुकेश असवाल ने बताया- इस तकनीक के उपयोग से ऑपरेशन के दौरान इम्प्लांट लगाने की सटिकता मिलती है। अभी मैनुअल ऑपरेशन में कई बार कुछ कमी रह जाती है तो उससे मरीज को बाद में थोड़ी परेशानी होती है। इस तकनीक से 100 फीसदी सटिकता के साथ इम्प्लांट लगाने से मरीजों को फायदा होता है। इससे मरीजों का ऑपरेशन के दौरान चीरा भी कम लगता है। ब्लड लॉस भी कम होने से मरीज की रिकवरी भी जल्दी होती है। संभवता मरीज का ऑपरेशन करने के 12 घंटे बाद ही उसे चलना-फिरना शुरू करवा देते है।

पात्र आवेदकों के आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति हेतु जोन स्तर पर लगाए जाएंगे हेल्प डेस्क

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने गुरूवार को नगर निगम मुख्यालय पर जोन उपायुक्त, सीएसआई की विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सफाईकर्मी भर्ती-2024 के तहत बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार, उपायुक्त कार्मिक कविता चौधरी, उपायुक्त (स्वास्थ्य) ओम प्रकाश थानवी उपस्थित रहे। आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि पात्र आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाने के लिये समुचित निर्देशन देने के लिये जोन स्तर पर हेल्प डेस्क लगाई जाये तथा पात्र आवेदकों की हर संभव मदद की जाये। सरकारी नौकरी हर युवा का सपना है इसलिये पात्र आवेदकों को आवेदन करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिये हेल्प डेस्क के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाई जाये। जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र आवेदक सफाईकर्मी भर्ती-2024 के अन्तर्गत आवेदन कर सके।